नईदुनिया

मध्यप्रदेश बनेगा वैश्विक फार्मा केंद्रः डॉ. यादव

ब्रिटेन की कंपनी की भारत में पहली इकाई पीथमपुर में स्थापित होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत आज दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है और इसमें मध्यप्रदेश की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य अब वैश्विक फार्मा हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में हेलियन समूह की पहली विनिर्माण इकाई के भूमिपूजन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने रिमोट के माध्यम से परियोजना का सांकेतिक भूमिपूजन किया। यह इकाई लगभग दो हजार करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जा रही है। इस परियोजना से लगभग एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कंपनी द्वारा इकाई में तीस प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां लागू हैं और राज्य सरकार उद्योग स्थापना से उत्पादन तक हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। हेलियन समूह ने भारत में अपनी पहली विनिर्माण इकाई के लिए मध्यप्रदेश के पीथमपुर को चुना है। कंपनी लगभग चालीस एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक उत्पादन इकाई स्थापित कर रही है, जहां मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण होगा।

कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि यह इकाई भारत सहित एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को निर्यात केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी। कार्यक्रम में राज्य सरकार और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कंपनी ने मध्यप्रदेश में निवेश के लिए सरकार के सहयोग की सराहना की और भविष्य में विस्तार की संभावनाएं भी जताई।

मध्यप्रदेश में 7.63 लाख से अधिक बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि, एचपीवी वैक्सीनेशन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक किया पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश के शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है। राज्य में अब तक 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है, जिससे उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

श्री शुक्ल ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, शिक्षकों तथा जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी और बेहतर समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने प्रदेश की बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

यह देशव्यापी अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को एचपीवी संक्रमण से होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। मूल रूप से 90 दिनों के लिए निर्धारित यह अभियान मध्यप्रदेश में केवल 60 दिनों में ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की दक्षता को दर्शाता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस अभियान की सफलता में व्यापक जनजागरूकता, सूक्ष्म कार्ययोजना, सतत मॉनिटरिंग और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की अहम भूमिका रही है।

मतदान अधिकार से कोई पात्र वंचित न रहे, अपात्र को सूची से हटाना जरूरी : राज्य निर्वाचन आयुक्त

- मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता पर जोर, समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि मतदान सबसे पवित्र लोकतांत्रिक अधिकार है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता इस अधिकार से वंचित न रहे।

साथ ही यह भी जरूरी है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची के माध्यम से मतदान का उपयोग न कर सके। वे नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए तथा इसकी सतत निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों को पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

आयुक्त ने यह भी कहा कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर नाम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सुपरवाइजर की नियुक्ति कर कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण पर जोर दिया। साथ ही डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

दावे-आपत्तियों और अपील से जुड़े सभी प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण अनिवार्य बताया गया। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह ने जानकारी दी कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे, उनका निराकरण 25 जून तक किया जाएगा तथा अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को होगा। बैठक में विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भोपाल के कोर्टयार्ड बाय मैरियट का खाद्य लाइसेंस निलंबित

- किचन में चूहे मिले
- वेज और नॉनवेज साथ रखा
- सफाई व्यवस्था पूरी तरह फेल
- खाद्य नियमों की अनदेखी
- गंभीर खामियां उजागर
- होटल का फूड लाइसेंस निलंबित

चूहों ने उतार दी फाइव स्टार होटल की चमक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। होटल में चूहों की मौजूदगी की शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई।

डीबी सिटी स्थित डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में हुई जांच के दौरान अधिकारियों को होटल के स्टोर और किचन क्षेत्रों में चूहों की मौजूदगी मिली। इतना ही नहीं, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड की जांच में भी परिसर में चूहों की समस्या की पुष्टि हुई। निरीक्षण दल ने होटल की विभिन्न रसोइयों में साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को बेहद खराब पाया।

जांच के दौरान कई अन्य गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि होटल में उपयोग किए जा रहे शुगर सैशे एक तृतीय पक्ष निर्माण इकाई से लिए जा रहे थे, जिन्हें खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं किया गया था।

इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना किसी पृथक्करण के एक साथ संग्रहित किया जा रहा था, जिससे खाद्य दूषण का खतरा बढ़ सकता था।

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि होटल की भंडारण सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थीं। खाद्य पदार्थों को दूषण से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग और खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण) विनियम-2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन भी अपर्याप्त मिला।

*निरीक्षण रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों की संवीक्षा के बाद केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियों तथा केंद्रीय लाइसेंस **क्रमांक 11421999000174** को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।*

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश मानी जा रही है कि नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है।

गर्भावस्था में समय पर जांच से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चितः उप मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है । राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है । उन्होंने अपील की कि 9 जून को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष शिविरों में सभी गर्भवती महिलाएं जांच परामर्श और उपचार का लाभ लें । उन्होंने कहा कि समय पर प्रसवपूर्व जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है । जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है । वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14.31 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया जिनमें से 10.25 लाख की प्रसवपूर्व जांच की गई । यह कुल पंजीकृत महिलाओं का लगभग 72 प्रतिशत है । जांच के दौरान 2.94 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था के रूप में चिन्हित किया गया जिनमें से 2.60 लाख महिलाओं को आवश्यक उपचार और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई गईं ।

अपर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर 9 जून को सभी जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे । इनमें गर्भवती महिलाओं की जांच पंजीयन उपचार और फॉलोअप की व्यवस्था रहेगी ।

शिविरों में रक्तचाप हीमोग्लोबिन शुगर एचआईवी हेपेटाइटिस बी सिफलिस सहित विभिन्न जांचें की जाएंगी । जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क दवाएं और एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी । आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मी सक्रिय भूमिका निभाएंगे ।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

भविष्य की खेती पर होगा ...

भारत की अध्यक्षता के दौरान 2016 में स्थापित ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंच आज अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की अध्यक्षता में अब तक कृषि कार्य समूह की आठ बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। इंदौर में होने वाली बैठकों में इन विषयों को और आगे बढ़ाते हुए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस लघु और सीमांत किसानों पर रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसानों के सामने जोत का छोटा आकार, सीमित संसाधन और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत घटाने, अनुसंधान के लाभों को किसानों तक पहुंचाने, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भूमिका को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यबल में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि युवा नई तकनीकों और नवाचार को तेजी से अपनाने में सक्षम हैं। 12 जून को 'महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा' विषय पर विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की चार प्रमुख प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा और पोषण, कृषि व्यापार एवं सहयोग, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि तथा नवाचार और अनुसंधान साझेदारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और बाजार पहुंच को बढ़ाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन को कृषि के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी स्थितियां किसानों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में रीजेनेरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि मिट्टी और पर्यावरण की गुणवत्ता भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके।

खाद्य अपव्यय को भी एक बड़ी वैश्विक समस्या बताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर वर्ष लगभग एक अरब टन खाद्यान्न बर्बाद होता है, जो न केवल संसाधनों की हानि है बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भी एक प्रमुख कारण है। इस दिशा में भंडारण, परिवहन और सप्लाई चेन में सुधार के उपायों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं के विकास को गति दी जा रही है, जिसका दायरा अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी क्रांति का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अब तक 9.80 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। इससे किसानों की जानकारी एकीकृत रूप में उपलब्ध हो रही है और योजनाओं, ऋण तथा अन्य सेवाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सलाह, संसाधन प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक के कार्यक्रम के तहत 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की अधिकारी स्तर की बैठकें होंगी, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें भविष्य के सहयोग और साझा रणनीति का खाका प्रस्तुत किया जाएगा।

सहमति से बने संबंध ...

इसके खिलाफ उम्मीदवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित व्यक्ति और शिकायतकर्ता पड़ोसी थे और लंबे समय तक रिश्ते में रहे थे। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और मामला लोक अदालत में समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए उम्मीदवार की नियुक्ति पर पुनर्विचार का आदेश दिया और उसके पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

तृणमूल कांग्रेस के 20 ...

इसी बीच राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ दी है। उन्होंने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए तथा भाजपा की नीतियों की सराहना की। राज्यसभा के अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनका कार्यकाल वर्ष 2029 तक था।

इधर तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने भी कुछ नेताओं के आरोपों से सहमति जताई है और पार्टी में जारी घटनाक्रम को गंभीर बताया है। इसी बीच पार्टी ने बागी गुट को मान्यता देने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पार्टी की मुख्य सचेतक काकोली घोष ने कहा कि निर्णय विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और संगठन में बड़ी राजनीतिक हलचल जारी है।

इंटरपोल रेड नोटिस वाले 3 वन्यजीव तस्करों पर 2 लाख का इनाम घोषित

***नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः** मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत वन्यजीव मुख्यालय ने इंटरपोल द्वारा रेड नोटिस जारी तीन फरार अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों की गिरफ्तारी और उनके संबंध में सूचना देने वालों के लिए कुल 2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) की भोपाल इकाई द्वारा वर्ष 2015 में दर्ज एक मामले में बाघ के अवैध शिकार और उसके अंगों की अंतरराज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोपी जे.ई. तमांग (दिल्ली) और ढरके लामा (काठमांडू, नेपाल) पिछले लगभग दस वर्षों से फरार हैं। इसी तरह शिवपुरी इकाई के कछुए एवं घड़ियाल तस्करी प्रकरण में आरोपी अल हज़ मोहम्मद शफ़ीकुल इस्लाम उर्फ रहमान तालुकदार (ढाका, बांग्लादेश) भी फरार है। तीनों के खिलाफ न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं।*

इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए इंटरपोल ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। वन्यजीव मुख्यालय ने जे.ई. तमांग पर 1 लाख रुपये तथा अन्य दो आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

विभाग ने आमजन से अपील की है कि इन आरोपियों के संबंध में कोई भी जानकारी दिए गए संपर्क नंबरों पर साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

मप्र पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, चार दिनों में 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगातार सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। चोरी, ठगी और नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए चलाए गए विशेष अभियानों के तहत पिछले चार दिनों में पुलिस ने 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चोरी एवं ठगी गई संपत्ति बरामद की है तथा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ग्वालियर में कोतवाली पुलिस ने हॉलमार्क कराने के नाम पर ग्राहकों का सोना लेकर फरार हुए ज्वेलर्स संचालक और उसके साथी को मेरठ से गिरफ्तार कर करीब 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए। डबरा सिटी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर फर्जी लूटकांड का खुलासा कर चार आरोपियों को पकड़ते हुए 49.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। महाराजपुरा पुलिस ने 2023 की चोरी का खुलासा कर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित करीब 8 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की।

मुरैना में देवगढ़ थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और 55 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में चार आरोपियों को पकड़कर 15 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए गए। देवास में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 12.50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई। भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में नकबजनी के मामले में सात लाख रुपये के आभूषण बरामद हुए, वहीं इंदौर में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर चार लाख रुपये की चोरी का खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी, साइबर तकनीक और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना है।

समीक्षा बैठक ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश, पारदर्शिता पर मंत्री ने दिया जोर...

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता जरूरीः पटेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। वे विकास भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में इस तिमाही में व्यय कम हुआ है, वहां कार्यों में तेजी लाई जाए और भारत सरकार से जुड़े मामलों पर लगातार फॉलो-अप किया जाए। उन्होंने 'जन मन' योजना की किस्त समय पर जारी करने, सोशल ऑडिट के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने तथा 'बीबी रामजी योजना' के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बजट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री पटेल ने विभागीय संरचना को मजबूत बनाने के लिए पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादकः डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादकः अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com